

आय से 70 फीसदी अधिक संपत्ति! रिटायर्ड इंजीनियर पर एसीबी का शिकंजा, नौ साल की जांच में खुले करोड़ों के खेल के संकेत

सूरत शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने सरकारी महकमों में हलचल मचा दी है। सूरत नगर निगम के तकनीकी विभाग में वर्षों तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ संभाल चुके सेवानिवृत्त सहायक अभियंता रसिकभाई मगनभाई पटेल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। एसीबी के अनुसार संबंधित अधिकारी ने अपनी ज्ञात और वैध आय की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक संपत्ति एकत्रित की, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया गया है।

यह मामला केवल एक अधिकारी की संदिग्ध संपत्ति तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उन वित्तीय गतिविधियों की जांच के रूप में देखा जा रहा है जो लंबे समय तक सरकारी तंत्र की नजरों से दूर रहीं। एसीबी सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई से पहले कई स्तरों पर दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अधिकारी की

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: कांकेर में प्रेशर कुकर बम बरामद, सुकमा के जंगलों से हथियारों का जखीरा मिला

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों की लगातार बढ़ती सक्रियता और प्रभावी अभियान का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। राज्य के कांकेर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों के दौरान नक्सलियों को बड़ी साजिशों को विफल करते हुए विस्फोटक सामग्री, हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इन सफलताओं को सुरक्षा एजेंसियाँ नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही हैं, क्योंकि बरामद सामग्री का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने तथा क्षेत्र में भय और अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा सकता था।

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी अनहोनी को समय रहते टाल दिया। गड्ढाकल गांव के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए सचिंग अभियान के दौरान तीन किलोग्राम बनजी प्रेशर कुकर आईईटी बरामद किया गया। यह विस्फोटक अत्यंत खतरनाक श्रेणी का माना जाता है और इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि सुरक्षा बलों की आवाजाही के दौरान अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। यदि समय रहते इसकी पहचान नहीं होती तो यह किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकता था। जानकारों के अनुसार, क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान जवानों ने जंगलों और पहाड़ी भागों की सावधानीपूर्वक जांच की। इसी दौरान संदिग्ध स्थान पर छिपाकर रखा गया प्रेशर कुकर आईईटी मिला। विस्फोटक मिलने

बेटियों के सपनों को मिली नई उड़ान: एनटीपीसी इनोर के बालिका सशक्तिकरण मिशन का प्रेरणादायी समापन

सूरत जिले के इनोर स्थित एनटीपीसी परिसर में आयोजित बालिका सशक्तिकरण मिशन (जीईएम) 2026 का भव्य समापन उत्साह, आत्मविश्वास और नई उम्मीदों के साथ संपन्न हुआ। एक महीने तक चले इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ने ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों की बालिकाओं को केवल शिक्षा और कौशल ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पहचानने और उन्हें साकार करके का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। समापन समारोह में जब बालिकाओं ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उपस्थित अभिभावकों, अधिकारियों और अतिथियों की आंखों में गर्व और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पश्चिम-1) एवं सीईओ (यूपीएल) ई. सत्य फणि कुमार तथा सखी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती ई. सरोजा मुख्त अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दे रहा था, जहां हर ओर बालिकाओं की उपलब्धियों और उनके उज्वल भविष्य की चर्चा हो रही थी। समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम रहे। मंच पर आत्मविश्वास से भरी इन बेटियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सिंगल-यूज प्लास्टिक उन्मुलन और कचरा

प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके अभिनय, संवाद और प्रस्तुति में केवल कला ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारों की भावना भी दिखाई दी। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन प्रस्तुतियों का स्वागत किया। इसके अलावा बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से एक महीने के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभवों का प्रदर्शन किया। आत्मरक्षा के प्रदर्शन ने विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। छोटी-छोटी बालिकाओं को आत्मविश्वास की प्रदान किया। समापन समारोह में जब बालिकाओं ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उपस्थित अभिभावकों, अधिकारियों और अतिथियों की आंखों में गर्व और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पश्चिम-1) एवं सीईओ (यूपीएल) ई. सत्य फणि कुमार तथा सखी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती ई. सरोजा मुख्त अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दे रहा था, जहां हर ओर बालिकाओं की उपलब्धियों और उनके उज्वल भविष्य की चर्चा हो रही थी। समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम रहे। मंच पर आत्मविश्वास से भरी इन बेटियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सिंगल-यूज प्लास्टिक उन्मुलन और कचरा



के अनुसार अधिकारी के पास लगभग 68.98 लाख रुपये मूल्य की ऐसी संपत्ति पाई गई, जिसका संतोषजनक और वैध स्रोत उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रारंभिक गणना में यह राशि उनकी ज्ञात आय से 70.13 प्रतिशत अधिक पाई गई। भ्रष्टाचार के मामलों में आय से अधिक संपत्ति को सबसे गंभीर आरोपों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें यह जांच

जाता है कि किसी लोकसेवक ने अपनी सेवा अवधि के दौरान जितनी वैध आय अर्जित की, उसके मुकाबले उसके पास कितनी संपत्ति मौजूद है। यदि संपत्ति और आय के बीच असामान्य अंतर पाया जाता है और उसका वैध स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं होता, तो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। इसी आधार पर एसीबी ने

बरामदगी यह संकेत देती है कि नक्सली संगठन अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है।

पुलिस को अभियान के दौरान जंगल के भीतर संदिग्ध स्थानों पर छिपाकर रखी गई सामग्री मिली। तलाशी के दौरान एक इंसार रायफल, बड़ी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बरामद हथियारों में एक इंसार रायफल के अलावा 49 इंसार कारतूस, 12 एसएलआर कारतूस, 27 नग .303 कारतूस, 16 नग 8 एमएम कारतूस, 7 मस्केट कारतूस और 7 नग 12 बोर कारतूस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तीन इंसार मैग्जीन, वायरलेस उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले छह सेल, एक पांच और दो स्टील के डिब्बे भी बरामद किए गए।

सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी विस्फोटक सामग्री से जुड़ी रही। पुलिस को दो बंडल काँडेक्स वायर मिले, जिनकी कुल लंबाई लगभग 30 मीटर बताई जा रही है। काँडेक्स वायर का उपयोग आमतौर पर विस्फोटक उपकरणों को सक्रिय करने और नियंत्रित विस्फोट करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना ​​है कि इस सामग्री का उपयोग भविष्य में किसी बड़ी नक्सली कार्रवाई के लिए किया जा सकता था।

सुकमा लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित संचार सुविधाएं नक्सलियों को छिपने और अपनी गतिविधियां संचालित करने में मदद करती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर नक्सलियों के कई ठिकानों को ध्वस्त नहीं किए हैं और उनके प्रभावित क्षेत्रों को सीमित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद समय-समय पर जंगलों की जंगलों के भीतर हथियारों के भंडारण

को जांच के दायरे में रखा गया। इन सभी जानकारियों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के बाद एसीबी ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया।

मामले में सूरत शहर एसीबी के पुलिस निरीक्षक के.जे. धडुक द्वारा आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारी ने अपने पदा का लाभ उठाकर अनुचित आर्थिक संपत्ति अर्जित की। इसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब जांच एजेंसी इस मामले को केवल दर्ज एफआईआर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे वित्तीय नेटवर्क की तह तक पहुंचने की तैयारी में है।

एसीबी के अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में जांच का दायरा और व्यापक किया जाएगा। अधिकारी को चल और अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों, लॉकरों, निवेश योजनाओं और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड का भी गहन परीक्षण होगा। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि कहीं किसी रिश्तेदार, परिचित या अन्य व्यक्ति

इस मामले में आगे बढ़ते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान अधिकारी से जुड़े अनेक वित्तीय दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बैंक खातों के लेन-देन, निवेश योजनाओं, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, वाहन खरीद, विभिन्न प्रकार के वित्तीय व्यवहार और अन्य आर्थिक गतिविधियों

नासीरनगर की रहस्यमयी तोड़फोड़ ने खड़े किए कई सवाल मनपा की सफाई के बाद अब जांच के घेरे में पूरा घटनाक्रम

सूरत के कतारगाम क्षेत्र स्थित नासीरनगर में हुई कथित रहस्यमयी तोड़फोड़ की घटना ने पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। लगातार सामने आ रही खबरों, स्थानीय लोगों की शिकायतों और विभिन्न तरह की अटकलों के बीच अब सूरत महानगरपालिका प्रशासन ने पूरे मामले की आधिकारिक जांच कराने का निर्णय लिया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजन पटेल ने नगर आयुक्त को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है।

घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर नासीरनगर क्षेत्र में हुई कथित तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। स्थानीय लोगों के बीच इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका प्रशासन का दावा है कि उसकी टीम वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने नहीं गई थी। प्रशासन का कहना है कि संबंधित स्थान पर केवल सीमांकन यानी डिमांडेशन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी और इसी उद्देश्य से अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मामले ने तब और अधिक तूल पकड़ लिया जब विभिन्न माध्यमों में यह खबर सामने आने लगी कि सीमांकन की कार्रवाई के दौरान या उसके बाद क्षेत्र में तोड़फोड़ हुई। इन खबरों के बाद नगर निगम प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि

अब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महानगरपालिका की ओर से किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई। इसके अनुसार, मनपा प्रशासन ने केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि और संपत्ति की सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य किया था। प्रशासन के अनुसार, खान सर की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुसार वर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और कानून की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकें। यह मामला पटना के कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला

के नाम पर संपत्तियां तो नहीं खरीदी गईं। यदि ऐसी कोई बेनामी संपत्ति सामने आती है तो जांच की दिशा और अधिक गंभीर हो सकती है। सूत्रों का मानना ​​है कि इस मामले में केवल घोषित संपत्तियों की जांच पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए उन सभी आर्थिक गतिविधियों का भी परीक्षण किया जाएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध आरोपी अधिकारी से रहा है। एसीबी इस संभावना को भी खारिज नहीं कर रही कि जांच के दौरान अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताएं या अन्य संदिग्ध लेन-देन सामने आ सकते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच यह कार्रवाई चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। तकनीकी विभाग में लंबे समय तक कार्य कर चुके अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला कई लोगों के लिए अप्रत्याशित माना जा रहा है। वहीं कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है और पुराने मामलों को भी गंभीरता से खंगाला जा रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई भविष्य में अन्य मामलों की जांच के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

मामले में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अग्रिय स्थिति से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह एक सामान्य प्रशासनिक विशेषता होती है, जिसे कई संवेदनशील मामलों में अपनाया जाता है। लेकिन यदि सीमांकन के बाद किसी प्रकार की तोड़फोड़ हुई है, तो यह जांच का पटेल ने कहा कि कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न जनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और संपत्ति की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति रह सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौराहों, सीमा क्षेत्रों और विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं के संगम वाले स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हमेशा सरल नहीं होता। कई मामलों में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही क्या उसी आधार पर हाल की कार्रवाई की गई थी। यदि ऐसा है तो उस प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज और अभिलेखों का उपयोग किया गया। इन सभी पहलुओं की जांच अब प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी।



राजन पटेल का कहना है कि सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अग्रिय स्थिति से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह एक सामान्य प्रशासनिक विशेषता होती है, जिसे कई संवेदनशील मामलों में अपनाया जाता है। लेकिन यदि सीमांकन के बाद किसी प्रकार की तोड़फोड़ हुई है, तो यह जांच का पटेल ने कहा कि कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न जनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और संपत्ति की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति रह सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौराहों, सीमा क्षेत्रों और विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं के संगम वाले स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हमेशा सरल नहीं होता। कई मामलों में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही क्या उसी आधार पर हाल की कार्रवाई की गई थी। यदि ऐसा है तो उस प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज और अभिलेखों का उपयोग किया गया। इन सभी पहलुओं की जांच अब प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे मामले को तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें। इसमें सीमांकन की प्रक्रिया, संबंधित विभागों की भूमिका, मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी, पुलिस के उपस्थिति तथा घटना के दौरान हुई

सर्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में आय से अधिक संपत्ति के मामलों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि ऐसे मामलों में केवल रिकवरी या किसी एक घटना की जांच नहीं होती, बल्कि पूरे सेवा काल के दौरान अर्जित संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। यही कारण है कि एसीबी भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में गुजरात के प्रशासनिक तंत्र में चर्चा का विषय बन गई है।

फिलहाल एसीबी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे इस मामले की दिशा और गंभीरता को तय करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि रिटायर्ड सहायक अभियंता के खिलाफ दर्ज यह मामला भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है और इसकी प्रगति पर अब प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है।

मामले में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अग्रिय स्थिति से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह एक सामान्य प्रशासनिक विशेषता होती है, जिसे कई संवेदनशील मामलों में अपनाया जाता है। लेकिन यदि सीमांकन के बाद किसी प्रकार की तोड़फोड़ हुई है, तो यह जांच का पटेल ने कहा कि कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न जनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और संपत्ति की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति रह सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौराहों, सीमा क्षेत्रों और विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं के संगम वाले स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हमेशा सरल नहीं होता। कई मामलों में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही क्या उसी आधार पर हाल की कार्रवाई की गई थी। यदि ऐसा है तो उस प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज और अभिलेखों का उपयोग किया गया। इन सभी पहलुओं की जांच अब प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे मामले को तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें। इसमें सीमांकन की प्रक्रिया, संबंधित विभागों की भूमिका, मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी, पुलिस के उपस्थिति तथा घटना के दौरान हुई

सर्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में आय से अधिक संपत्ति के मामलों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि ऐसे मामलों में केवल रिकवरी या किसी एक घटना की जांच नहीं होती, बल्कि पूरे सेवा काल के दौरान अर्जित संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। यही कारण है कि एसीबी भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में गुजरात के प्रशासनिक तंत्र में चर्चा का विषय बन गई है।

फिलहाल एसीबी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे इस मामले की दिशा और गंभीरता को तय करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि रिटायर्ड सहायक अभियंता के खिलाफ दर्ज यह मामला भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है और इसकी प्रगति पर अब प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है।

अदालत की शरण में पहुंचे खान सर, गिरफ्तारी की आशंका के बीच अग्रिम जमानत की मांग से बड़ी कानूनी हलचल



जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुसार वर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और कानून की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकें। यह मामला पटना के कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला

उनके निजी सुरक्षा कर्मियों से जुड़े कुछ कथित बयानों और घटनाक्रमों के आधार पर दर्ज किया गया है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। खान सर के साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वे भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्हें आशंका है कि पुलिस कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी कारण उन्होंने अदालत से कानूनी संरक्षण की मांग की है।

इस पूरे मामले ने इसलिए भी अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि डिजिटल शिक्षा जगत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनकी निजी सुरक्षा कर्मियों को तैयारी कराने वाले उनके वीडियो देशभर में करोड़ों बार देखे जाते रहे हैं। बिहार सहित देश के अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं और उनकी शिक्षण शैली को सरल

एवं प्रभावी मानते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला स्वाभाविक रूप से अनेक वित्तीयपक्षों का कहना है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति को जांच से बचाना नहीं होता, बल्कि उसे अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करना होता है। यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और उसके फरार होने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, तो अदालत कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान कर सकती है। हालांकि यह पूरी तरह अदालत के विवेक और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष भी अदालत में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस जांच से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। अदालत दोनों पक्षों के दलीलों सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। खान सर के समर्थक उनके पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जबकि कई लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर

रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर बहस का दौर जारी है और लोग अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और जांच जारी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल खान सर का अदालत पहुंचना और अग्रिम जमानत की मांग करना इस प्रकरण को और अधिक चर्चा के केंद्र में ले आया है।

एक सबकी निगाहें पटना की अदालत पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तारी से राहत मिलती है या नहीं। अदालत का निर्णय न केवल इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कानूनी और सामाजिक बहस को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल छात्रों, समर्थकों, कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है—क्या खान सर को अदालत से राहत मिलेगी या उन्हें जांच प्रक्रिया का सामना किसी अन्य परिस्थिति में करना पड़ेगा। इसका उत्तर अब न्यायालय के आगामी आदेश में ही सामने आएगा।

साँइल हेल्थ कार्ड : भूमि का एक्स-रे

गुजरात में पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक किसानों ने निःशुल्क साँइल हेल्थ कार्ड बनवाए

▶▶ चालू वर्ष में गुजरात में 2.18 लाख साँइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य

▶▶ साँइल हेल्थ कार्ड का प्रभाव : भावनगर के किसान श्री हिरनभाई का उर्वरकों का उपयोग 370 किलोग्राम घटा; फिर भी उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा

▶▶ साँइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों का पालन करने से सुरेंद्रनगर के श्री अरुणभाई की जमीन अधिक उपजाऊ बनी

▶▶ गुजरात में साँइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत गुजरात में साँइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत : 12 तत्वों का होता है परीक्षण

गांधीनगर : भावनगर के गारियाधार गांव के किसान श्री हिरनभाई नाकराणी के पास 12 बीघा जमीन है। वे वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं। कपास की फसल में वे हर वर्ष 400 किलोग्राम यूरिया और 290 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करते थे। इससे उनकी खेती की लागत अधिक रहती थी और उत्पादन केवल 200 मन तक ही सीमित रहता था।

श्री हिरनभाई ने ग्रामसेवक की सलाह पर भावनगर की साँइल टेस्टिंग प्रयोगशाला

में अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। मिट्टी परीक्षण के बाद साँइल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिशों के अनुसार उन्होंने अपने खेत में यूरिया का उपयोग 180 किलोग्राम तथा डीएपी का उपयोग 140 किलोग्राम कर दिया। इस प्रकार 220 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम डीएपी की बचत हुई, जिससे खेती की लागत लगभग आधी हो गई। साथ ही वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन भी 200 मन से



बढ़कर 281 मन हो गया। श्री हिरनभाई कहते हैं, "पहले हम अंधेरे में तीर चलाते थे। अधिक उत्पादन पाने के लिए अंधाधुंध उर्वरकों की बोरियां खेत में डालते रहते थे और जमीन को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन जब हमारे हाथ में साँइल हेल्थ कार्ड आया, तब पता चला कि यह तो हमारी जमीन की एक्स-रे रिपोर्ट है। अब हम सिफारिश के अनुसार लक्ष्य आवश्यकता होती है, उतना ही उर्वरक उपयोग करते हैं। इससे लागत

आधी हो गई है और फसल भरपूर होने लगी है।" श्री हिरनभाई के हिरनभाई की तरह राज्य के लाखों किसानों ने पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक साँइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनवाए हैं। चालू वर्ष में भी राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से जमीन के 2.18 लाख नमूनों की जांच कर साँइल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साँइल हेल्थ कार्ड से खेती की लागत कम

होने और आय बढ़ने के अलावा भूमि अधिक स्वस्थ और उपजाऊ भी बनती है। सुरेंद्रनगर जिले के लिखतर तहसील के किसान श्री अरुणभाई मणिगा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "साँइल हेल्थ कार्ड के कारण मेरी जमीन की जांच हुई और मैंने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप मेरे खेत की कठोर हो चुकी जमीन नरम बताने है कि साँइल हेल्थ कार्ड से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित

हिरेनभाई और श्री अरुणभाई जैसे अनेक किसानों की खेती में साँइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से बड़ा परिवर्तन आया है। साँइल हेल्थ कार्ड क्या है और किसान को इससे क्या लाभ होता है? गांधीनगर साँइल टेस्टिंग लैब की सहायक कृषि निदेशक श्रीमती पारुल परमार बताती हैं कि साँइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेश जैसे 6 प्रमुख तत्वों तथा कॉपर, आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे 6 सूक्ष्म तत्वों सहित कुल 12 मानकों का पृथक्करण किया जाता है। इस पृथक्करण के आधार पर किसानों को उर्वरकों के उपयोग संबंधी सिफारिशों दी जाती हैं। इन सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने से अनावश्यक खर्च रुकता है और जमीन भी स्वस्थ बनी रहती है। गुजरात में वर्तमान में मिट्टी परीक्षण के लिए 21 प्रयोगशालाएं और एक सूक्ष्म तत्व प्रयोगशाला कार्यरत हैं।

साँइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें? सहायक कृषि निदेशक श्री सापरिया बताते हैं कि साँइल हेल्थ कार्ड से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित

पद्धति से मिट्टी का नमूना लेना अत्यंत आवश्यक है। खेत की मेड़, रास्ते, पानी भरने वाले क्षेत्र अथवा पेड़ों की छाया से दूर रहकर एक हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 20 अलग-अलग स्थानों से जिगा-जैग पद्धति द्वारा 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर नमूना लेना चाहिए। एकत्रित मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर चार भागों में बांटना चाहिए और उनमें से दो भाग अलग कर देने चाहिए। इसके बाद शेष मिट्टी को पुनः मिलाकर उसमें से 500 ग्राम मिट्टी का नमूना परीक्षण के लिए भेजना चाहिए। इस प्रक्रिया से परीक्षण का परिणाम अधिक सटीक प्राप्त होता है। साँइल हेल्थ कार्ड की अवधारणा और विस्तार वर्ष 2003-04 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि राज्य में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण धरती माता अपनी उर्वरता खो रही है। उन्होंने विचार किया कि यदि मनुष्य के शरीर की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए जा सकते हैं, तो धरती माता के स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं की जा सकती? इसी विचार से 'साँइल हेल्थ कार्ड योजनी' का जन्म हुआ। गुजरात ने देश में सबसे पहले यह प्रयोग

12 वर्षों का लंबा संघर्ष और पिता की आंखों में खुशी के आंसू : आगरा के मासूम बच्चे के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल बना 'देवदूत'

जहां सारी आशाएं टूट गई थीं, वहां गुजरात सरकार ने दिया सहारा उत्तर प्रदेश के गरीब किसान के बेटे की जटिल सर्जरी सफल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पानशेरिया के नेतृत्व में गुजरात सरकार की प्रज्ञानोन्मुखी स्वास्थ्य नीति और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक बार फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में देखने को मिला है। सिविल अस्पताल के बाल रोग (पीडियाट्रिक सर्जरी) विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार के 12 वर्षीय बालक को नया जीवन दिया है। मात्र 25 दिन की नवजात अवस्था की उम्र में कुत्ते के हमले का शिकार बने इस बच्चे के जननांग का 12 वर्ष बाद सफल रिक्टस्ट्रिक्टिव सर्जरी द्वारा फिर से सामान्य किया गया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने भी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सिविल की पूरी मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात सरकार के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज देश और दुनिया भर के मरीजों को ऐसी जटिल चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी सुरेश यादव का पुत्र जब मात्र 25 दिन का था, तब एक कुत्ते ने उस पर हमला कर उसके बाह्य जननांग को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, उसकी परेशानियां भी असहनीय होती गईं। बच्चे को पेशाब करने में अत्यंत कठिनाई होती थी और उसके जननांग का विकास



पूरी तरह रुक गया था। कई स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः यह परिवार उम्मीद लेकर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचा। बच्चे को 1 मई, 2026 को भर्ती किए जाने के बाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग की सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी ने जांच की। जांच में पता चला कि बच्चे के दोनों वृषण (टेस्टिस)

अनुपस्थित थे, लिंग अंदर की ओर दब गया था तथा मूत्रमार्ग का छिद्र अत्यंत संकरा हो गया था। सभी चुनौतियों के बावजूद 6 मई, 2026 को डॉ. राकेश जोशी और प्रोफेसर डॉ. जयश्री रामजी के नेतृत्व में तथा एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. मृणालिनी और उनकी टीम की देखरेख में जटिल जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी (जेनिटल रिक्टस्ट्रिक्टिव सर्जरी) के साथ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी

सफलतापूर्वक की गई। 14 दिनों की सघन देखरेख के बाद जब कैथेटर (पेशाब की नली) हटाई गई, तब बच्चे ने बिना किसी पीड़ा के सामान्य रूप से पेशाब किया। वर्षों बाद अपने बेटे को सामान्य स्थिति में देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने गुजरात सरकार तथा सिविल अस्पताल के चिकित्सकों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल ब्रंचक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं रेलवे बोर्ड के पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून 2026 को मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर (DRH/BVP) के उद्यान परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों एवं कर्मचारियों में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं चिकित्सकों द्वारा पर्यावरण



संरक्षण की सामूहिक शपथ ग्रहण कर किया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों को चार टीमों - टीम A, टीम B, टीम C एवं टीम D - में विभाजित कर पर्यावरण विषयक विभिन्न रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 'Carry Water

Carefully Challenge", "Waste Segregation Competition", "Green Treasure Hunt" तथा "Environment Puzzle Challenge" जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल संरक्षण, कचरा पृथक्करण, पर्यावरणीय जागरूकता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, खेल भावना एवं टीमवर्क का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में सक्रिय सहभागिता निभाई तथा पर्यावरण संरक्षण से

जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को व्यवहारिक रूप से आत्मसात किया। सभी प्रतियोगिताओं के अंकों के समेकित मूल्यांकन के उपरांत डॉ. मणिगा के नेतृत्व वाली टीम D ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा "ग्रीन चैंपियन-2026" का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को कार्यक्रम के समापन अवसर पर सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन एवं सहभागिता का माध्यम बना, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व एवं जन-जागरूकता को सशक्त बनाने में भी सफल रहा। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं समूह छायाचित्र के साथ हुआ।

850 ग्राम का खेल खत्म: खाद्य तेल पैकेजिंग में बड़ा बदलाव, अब तय मानकों में ही बिकेगा तेल

देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बाजार में लंबे समय से चल रही भ्रामक पैकेजिंग व्यवस्था पर सख्ती दिखाई है। अब खाद्य तेल कंपनियों अपनी सुविधा के अनुसार 850 ग्राम, 900 ग्राम या 910 ग्राम जैसे असामान्य पैक आकारों में उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं कर सकेंगी। सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए स्पष्ट मानक तय कर दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं ने अक्सर यह अनुभव किया कि खाद्य तेल के पैकेटों का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जबकि कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक बदलाव दिखाई नहीं देता था। कई कंपनियों ने एक लीटर या

एक किलोग्राम के पारंपरिक पैक की जगह 850 ग्राम, 900 ग्राम, 910 ग्राम या अन्य असामान्य मात्रा वाले पैक बाजार में उतारने शुरू कर दिए थे। पहली नजर में उपभोक्ता को यह पैकेट सामान्य आकार का प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविक मात्रा कम होने के कारण प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर कीमत अधिक पड़ती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए नए मानक लागू करने का फैसला किया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब खाद्य तेल केवल निर्धारित मानक पैक आकारों में ही बेचे जा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और भ्रमपूर्ण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। नए नियमों के तहत खाद्य तेलों की बिक्री 200 ग्राम, 500 ग्राम,

1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के मानक पैक आकारों में की जाएगी। इन मानकों का पालन देशभर में खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स, वितरकों और आयातकों को करना होगा। इससे बाजार में उपलब्ध उत्पादों के आकार में एकरूपता आएगी और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नियम केवल किसी एक प्रकार के तेल तक सीमित नहीं हैं। इनका दायरा खाद्य तेलों की लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों को कवर करता है। पाप ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल, राइस ब्राउन ऑयल, कॉटनसीड ऑयल और कॉर्न ऑयल सहित इनके मिश्रित उत्पादों पर भी यह नियम लागू होगा। इससे

पूरे खाद्य तेल उद्योग में एक समान मानक स्थापित होने की उम्मीद है। सरकार ने उद्योग जगत को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय भी दिया है। इस अवधि के दौरान कंपनियों अपनी पैकेजिंग, लेबलिंग और वितरण व्यवस्था में आवश्यक बदलाव कर सकेंगी। इसके बाद निर्धारित मानकों के विपरीत पैकेजिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उद्योग जगत को पर्याप्त समय दिए जाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बदलाव सुचारू रूप से लागू हो और बाजार में किसी प्रकार की आपूर्ति संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। नए नियमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी पैकेट पर तेल की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में दर्शाई जाती है, तो उसके समतुल्य वजन का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर साबरमती लोकोशेड एवं रेलवे हॉस्पिटल में व्यापक वृक्षारोपण

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत विभिन्न रेल परिसरों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। साबरमती स्थित लोकोमोटिव शेड में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (Sr. DME) श्री एस. पी. गुला के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुपरवाइजरों, तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य रेलकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री गुला ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सभी कर्मचारियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।



इसी क्रम में मंडल रेलवे हॉस्पिटल, साबरमती में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज देव के नेतृत्व में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। डॉ. देव ने कहा कि स्वच्छ वायु और हरित वातावरण अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है तथा अस्पताल परिसर को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए ऐसे

प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा ट्रेक किनारे भी नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर एवं जामुन जैसे स्वदेशी पौधों का रोपण किया गया। अहमदाबाद मंडल भारतीय रेलवे के "नेट जीरो कार्बन एमिशन" लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत एवं हरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी असारवा और आगरा केंद्र के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए असारवा और आगरा केंद्र के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 01909/01910 असारवा-आगरा केंद्र स्पेशल (कुल 16 ट्रेप) ट्रेन संख्या 01909 असारवा-आगरा केंद्र स्पेशल 09 जून से 28 जुलाई 2026 तक प्रति मंगलवार असारवा से प्रतिदिन 15.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07.45 बजे आगरा पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01910 आगरा केंद्र-असारवा स्पेशल 08 जून से 27 जुलाई 2026 तक प्रति सोमवार आगरा केंद्र से प्रतिदिन 18.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11.10 बजे असारवा पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगारपुर सिटी, रूपबास और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन सं. 01909 की बुकिंग 07 जून 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के उठारवा, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।



मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया। महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में अहमदाबाद से गांधीनगर तक कुल 37.60 किलोमीटर लंबाई में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तीनों चरणों (फेज) के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर के निकट निर्माणधीन गुजरात टेकनोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीटीयू) के नए कैम्पस के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ कराई स्थित नर्मदा नहर से पीडीईयू, पीडीईयू से शाहपुर ब्रिज तथा शाहपुर ब्रिज से चिलोडा ब्रिज तक कुल 17.20 किलोमीटर लंबाई के कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा प्रगति पर हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने से गांधीनगर



महानगर एवं गिफ्ट सिटी क्षेत्र के नागरिकों को एक आकर्षक पर्यटन स्थल उपलब्ध होगा। साथ ही; रोड कनेक्टिविटी से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी और अधिक सुदृढ़ होंगी। परियोजना के तीनों फेज का कार्य वर्ष 2027 के अंत तक पूर्ण होने तथा लोकावकाश में 100 एकड़ भूमि पर निर्मित

हो रहे जीटीयू भवन का कार्य आगामी अक्टूबर तक पूरा होने का अनुमान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठी तथा वरिष्ठ सचिवों ने आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान की।